

cation whereas the one in question is a U. K. one. They are two different things.

Extension of Commercial Broadcast Services on A. I. R.

*1713. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) when the proposal to extend the commercial broadcasting services of All India Radio to Calcutta, Delhi and Madras will finally materialise ;

(b) the likely annual incomes from these proposed extensions ; and

(c) the success achieved by the Bombay, Poona and Nagpur-projects ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SETPATHY) : (a) The proposal to extend the Commercial Broadcasting Service to Calcutta, Delhi, and Madras is under examination of the Government and is likely to materialise soon.

(b) A very rough estimate puts the annual income from Calcutta, Delhi and Madras Centres at Rupees 40 lakhs, Rupees 30 lakhs and Rupees 15 lakhs respectively.

(c) The Bombay-Poona-Nagpur project has made a very promising beginning. A far bigger demand for time in excess of availability goes to prove to popularity and success of the Project.

श्री बेनी शंकर शर्मा : अध्यक्ष महोदय श्री माननीय उप-मंत्री महोदय ने कहा है कि शीघ्र कलकत्ता, मद्रास और अन्य शहरों में विज्ञापन प्रसार करने का काम आरम्भ किया जायगा। मैं समझता हूँ कि यह कार्य चन्दा कमेटी के सुझावी के अनुसार किया जा रहा है। चन्दा कमेटी नवम्बर, 1964 में गठित की गई थी, मार्च, 1967 में उसकी रिपोर्ट आपको मिली, ढाई वर्ष चन्दा कमेटी ने रिपोर्ट देने में लगाये, अब आप कितना समय लेंगे जिससे कि कलकत्ता मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद सरीखे शहरों में जहाँ से विज्ञापन प्रसार के कार्य से काफी आय होने की सम्भावना है, इस कार्य को शुरू किया

जा सके ? यह कहना कि बहुत जल्दी करेंगे बड़ा भ्रामक है। आपकी बहुत जल्दी का अर्थ हमें मालूम है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस निश्चित तिथि तक आप इन शहरों में विज्ञापन प्रसार काम आरम्भ कर देंगे।

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH) : It is to our advantage and in our national interest to start as early as we can, but the difficulty is about consoles. Whatever consoles are in our possession, we are trying to use them, and the rest are either to be manufactured by BEL or have got to be imported.

The second difficulty is about space. The present space available in the offices of the All India Radio is not enough to start new studios—studios for the purpose preparing spots. This takes time. We are training our best in this regard.

श्री बेनी शंकर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस विज्ञापन प्रसार की कला को सीखने के लिए क्या हमारे आकाशवाणी के कुछ अफसरों को विदेशों में भेजा गया था ? यदि भेजा गया था, तो कितने अफसरों को भेजा गया किन किन देशों में वे गये और उस पर कितना खर्चा हुआ ? मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ—रेडियो सीलोन का उदाहरण हमारे सामने है। रेडियो सीलोन द्वारा प्रसारित विज्ञापन तथा उसके मध्य में दिये गये संगीत आदि भारत के रेडियो सुनने वालों में बहुत लोकप्रिय हुए थे, क्या उसी पद्धति की आधार पर माननीय मंत्री जी भी यहां शीघ्रातिशीघ्र व्यापारिक प्रसारण आदि का काम आरम्भ करेंगे, जिससे कि हमारी आय का इतना बड़ा स्रोत अवरोध न हो ? आप जानते हैं विदेश की बजट को पूरा करने के लिए हमें पोस्ट-कार्ड के दाम बढ़ाने पड़े हैं, लिफाफों के दाम भी बढ़ाने पड़े हैं, हम हर चीज पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारी आय का बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, उस को हम जल्द से जल्द काम में क्यों नहीं लाते ?

श्री के० के० शाह : मैं आपका बहुत शुक्र-गुजार हूँ कि आप भी चाहते हैं कि इसको बहुत

जल्दी शुरू किया जाय। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं आप यह कहें कि इसे जल्दी शुरू न करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसे जल्दी से जल्दी शुरू किया जायगा।

श्री बेनी शंकर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि कितने अफसर आपने बाहर भेजे हैं।

श्री के० के० शाह : किसी अफसर को भेजने की जरूरत नहीं थी।

SHRI RAJASEKHARAN : May I know whether the Government has got any proposal to bring Bangalore also under this commercial broadcasting service ?

SHRI K. K. SHAH : Yes, Sir.

SHRI S. K. TAPURIAH : Being in the hands of the Government, the advertising programmes of All India Radio generally tend to be in favour of the ruling party—there are quite a number of feature programmes and all that. May I ask from the Government whether they have considered the proposal of allowing the other political parties to buy time on its advertising programmes during elections, and whether they have also considered the proposal to sell time to various candidates for various election programmes ?

SHRI K. K. SHAH : The allegation is not correct. During the last general elections, we had approach the Election Commission for the purpose of allotting time to different parties, but unluckily no agreement could be arrived at. We have again written this time also to the Election Commission... (Interruptions)

श्री रवि राय : कांग्रेस के लिए ज्यादा समय मांगा, इसलिए एग्जीमेन्ट नहीं हो पाया। सबको समान समय देना चाहिए था।

SHRI K. K. SHAH : Till a settlement is arrived at, it is not possible to give time to any party.

SHRI S. K. TAPURIAH : What about

the second part of my question, about selling time ?

SHRI K. K. SHAH : It will not be sold to political parties.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : The hon. Minister has said that there is shortage of studios and that is why there is difficulty in extending this service. May I ask the hon. Minister whether there are any imported parts which are necessary to build the studios, and if not, if the entire studio can be build with India material, why is there the delay ?

SHRI K. K. SHAH : The BEL want us to place orders on them in advance so that they can prepare their production programme, because some items have to be imported. That means that we have to get financial sanction, and we are trying to get financial sanction in advance so that orders could be placed on a phased programme.

श्री श्रीकारलाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूँ कि विज्ञापन प्रसारण करने के लिए सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है और उस नीति के अन्तर्गत कितने विज्ञापन आये, उनमें से कितने विज्ञापन आपने खारिज किये और इस नीति को सरल करने के लिए आप कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ?

SHRI K. K. SHAH : We have laid down certain rules about accreditation. According to that accreditation, the advertising agencies are given accreditation. If no accreditation is given, then the next facility that is given is this ; if they are prepared to given a bank guarantee or pay in cash, they are given time then also. And the system that is followed is 'First come first served'.

SHRI INDER J. MALHOTRA : As far as the sales promotion for time for commercial broadcasting is concerned, may I know whether it will be entirely handled by AIR or some advertising agency or some other commission agents will be appointed for the purpose ?

SHRI K. K. SHAH : We do not

propose to give any sole selling agency to anybody.

श्री कंबरलाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इन कामर्शल ब्रॉडकास्ट के लिये आपने कोई कोड बनाया है कि कौन से एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट करने चाहिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी फारेन कम्पनीज की तरह से ब्रॉडकास्ट के लिए एडवर्टीजमेंट आये जिनको कि सरकार डिस्करेज करना चाहती हो ?

दूसरे यह कि क्या यह सही है कि इस ब्रॉडकास्ट से कुछ छोटे-छोटे अखबारों पर भी असर पड़ेगा ? यदि हाँ, तो इसके लिए सरकार ने क्या सोचा है, क्या योजना बनाई ?

श्री के० के० शाह : योजना बनाई है। इस बात को ध्यान में रखा गया है कि हमारे देश के उत्पादन करने वालों को इसमें ज्यादा सहूलियत मिले, उनके साथ कोई कम्पटीशन न हो।

दूसरे जो आपका डर है कि छोटे अखबारों को इससे नुकसान होगा तो उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, बड़े अखबारों को भी नुकसान नहीं हुआ है।

श्री कंबर लाल गुप्त : कोड आपने बनाया है क्या ?

के० के० शाह : जी हाँ, बनाया है।

SHRI MANUBHAI PATEL : Certain items which are contrary to Government policy cannot be allowed to be advertised through this commercial broadcasting. Has it come to the notice of the hon. Minister that some time back it had been reported that he had said that advertisement for liquors also would be broadcast over AIR? It appeared in the newspapers. May I know whether that is true ?

SHRI K. K. SHAH : I did not say that such advertisements would be broadcast. I said that that would be considered, but we have decided not to accept advertisements for liquors.

श्री कुशोक बाकुला : मैं सूचना मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ज्ञान है कि आजाद काश्मीर रेडियो से चलती जवान में भारत विरोधी प्रचार होता रहता है यदि हाँ, तो उसके जवाब में आकाशवाणी से लड़ाख की भाषा में कोई जवाब दिया जाता है ? यदि नहीं, तो उसको क्या वजह है ?

श्री के० के० शाह : यह प्रश्न तो कामर्शल एडवर्टीजमेंट के सम्बन्ध में है

SHRI S. S. KOTHARI : May I know how much foreign exchange is being drawn by Radio Ceylon and what efforts Government are making to popularise our radio programmes so that the popularity of radio Ceylon may go down and that of our programmes may go up ?

SHRI K. K. SHAH : I am glad to inform my hon. friend that the bookings of Radio Ceylon have gone down considerably.

SHRI S. S. KOTHARI : By what percentage ?

श्री श्रीकार लाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय भारत सरकार की यह नीति है कि छोटे-छोटे समाचार पत्रों, खास तौर पर भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अधिक से अधिक विज्ञापन दिये जायं लेकिन मेरे पास एक स्टेटमेंट आया है जिसके अनुसार, जो पब्लिक ग्रैंडरेंट-किंग्डम है उनके 80 प्रतिशत विज्ञापन विदेशी भाषाओं के पत्रों को मिले हैं और 20 प्रतिशत यहाँ की भाषाओं के पत्रों के मिले हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार कौन से ऐसे कदम उठाने जा रही है जिससे कि अधिक से अधिक विज्ञापन छोटे-छोटे समाचार-पत्रों को मिल सकें।

MR. SPEAKER : The main question relates to commercial broadcasting. But he is referring to newspapers. I do not know how it arises out of the main question.

SHRI SAMAR GUHA : May I know whether there will be complete freedom in regard to the nature of the advertisements, and if so, whether there is a possibility of even traders in obscene literature having freedom to advertise their literature or whether Government will impose any restriction on it ?

SHRI K. K. SHAH : I have said, there is a code and the code controls the advertisements. Therefore, obscene things will not be broadcast.

Nuclear Plant in Bihar

***1714 SHRI SHIVA CHANDRA JHA :** Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Government have made representation to the Central Government for setting up a nuclear plant in Bihar ;

(b) if so, the response of the Central Government thereto; and

(c) if not, how much money the Central Government have spent upto now for developing the nuclear potentiality in Bihar and what is the estimated amount to be spent on the same during the Fourth Plan period ?

THE DEPUTY MINISTER (DR. SAROJINI MAHISHI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) An expenditure of approximately Rs. 12.50 crores has been incurred so far on survey, prospecting, development and production of atomic minerals and establishment of an Uranium Ore Mill in Bihar State. A decision regarding the amount to be spent during the Fourth Plan period is yet to be taken.

श्री शिव चन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, खनिज पदार्थों के मामले में हिन्दुस्तान में बिहार नम्बर एक स्टेट है बल्कि कुछ खनिज पदार्थों में तो दुनिया में यह नम्बर एक स्टेट है। मैं तो इतना कहूँगा कि मोटे तौर पर भारत की अर्थ-व्यवस्था बिहार पर मुनहसिर करती है। यदि आज बिहार कोई दूसरा रास्ता अस्तियार कर ले तो भारत की सारी अर्थ-व्यवस्था पैराला-

इज्ड हो सकती है। लेकिन बिहार ऐसा करने नहीं जा रहा है किन्तु भारत सरकार कदम कदम पर बिहार की उपेक्षा कर रही है। कोसी कैकाल योजनाएँ इत्यादि वहाँ पर ठप्प हैं। इसी प्रकार से न्यूक्लियर प्लांट की भी उपेक्षा की जा रही है। इस संदर्भ में मैं प्रधान मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बिहार में न्यूक्लियर प्लांट बनाने में कौन सी खास खास हिचकिचाहटें हैं, उनकी क्या वज्रहात हैं और उनको दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? यदि कोई कदम नहीं उठा रही है, तो क्यों ?

DR. SAROJINI MAHISHI : The information given by the hon. Member in the first part of his question is not correct.

As regards the second part of his question, I would like to say that Bihar has not been neglected. The Uranium Corporation of India Ltd. has been established and work is being carried on in the Singbhum area, and in the copper belt of Singbhum and also Narwa Pahar and Bhatin etc. where uranium ores and reserves have been found out, further investigation and survey and further processing is being made in the light of the material collected and the study made by the particular committee set up by the Atomic Energy Commission.

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा सवाल था कि सरकार को क्या हेजिटेशन्स हैं, तथा हिचकिचाहट है और उनकी क्या वज्रहात हैं? क्या वहाँ पर रा-मैटीरियल नहीं है या क्या बात है, इसका जवाब नहीं दिया गया।

DR. SAROJINI MAHISHI : The Energy Survey Committee of India has made a survey and has stated that it is not economical to have atomic energy power plant in a place which is nearer the coal mines. And this has been taken into consideration that it is cheaper to produce power in those places with the help of the raw material that is available there, whether it be coal, oil or fossil fuel, rather than with atomic energy plants. It is based on this consideration that there is no atomic energy plant in Bihar.